

President's Address-laid

SECRETARY-GENERAL: Sir, I beg to lay on the Table a copy of the President's Address (Hindi and English versions) to both the Houses of Parliament assembled together on the 31st January, 2025.

माननीय सदस्यगण,

संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अभी दो माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75 वीं वर्षगांठ मनाई है, और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतन्त्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नयी ऊंचाई देगा। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबासाहेब आंबेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करती हूँ।

माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ, भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में पुण्य स्नान कर चुके हैं। मैं मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोया है। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वो लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ।

माननीय सदस्यगण, भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में तीन गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है। और इन निर्णयों में देश के गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए तीन करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पांच लाख छत्तीस हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों को उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक दो करोड़ पच्चीस लाख सम्पत्ति कार्ड जारी किए हैं। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने में जारी हुए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीनों में इक्तालीस हजार करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हुआ है। जनजातीय समाज के पांच करोड़ लोगों के लिए ?धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष? अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए अस्सी हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सत्तर वर्ष और उससे अधिक उम्र के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। इन्हें हर वर्ष पांच लाख रुपये का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा दस लाख रुपए से बढ़ाकर बीस लाख रुपए कर दी गई है। मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। एक करोड़ युवाओं को शीर्ष पांच सौ कंपनियों में इंटरशिप के अवसर भी दिये जाएंगे। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। सहकार से समृद्धि की भावना पर चलते हुए सरकार ने ?त्रिभुवन?

सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में पच्चीस हज़ार बस्तियों को जोड़ने के लिए सत्तर हज़ार करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आज जब हमारा देश अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष मना रहा है, तब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके विजन का पर्याय बनी हुई है। देश में अब इकहत्तर वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही हैं, जिनमें पिछले छह माह में ही सत्रह नई वंदे भारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है। ?वन नेशन-वन इलेक्शन? और ? वक्रफ़ अधिनियम संशोधन? जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए हैं।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है। विकसित भारत के विजन में... जनभागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है... देश की आर्थिक उन्नति का रोडमैप है, डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नॉलाजी की ताकत है, और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का आधार है। मेरी सरकार के प्रयासों के बल पर भारत, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। विकसित भारत की उड़ान को हमारे संविधान के आदर्शों का सतत मार्गदर्शन मिलता रहे, इसके लिए सरकार ने सेवा, सुशासन, समृद्धि और स्वाभिमान, इन प्रमुख सिद्धांतों को गवर्नेंस के केंद्र में रखा है। सरकार reform, perform और transform के अपने संकल्प को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। मेरी सरकार का मंत्र है - सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ...और इस मंत्र का एक ही लक्ष्य है - विकसित भारत का निर्माण।

माननीय सदस्यगण, जब देश के विकास का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मिलने लगता है तभी विकास सार्थक होता है। यही अंत्योदय की वो भावना है जिसके प्रति मेरी सरकार संकल्पित रही है। गरीब को गरिमापूर्ण जीवन मिलने से उसमें जो सशक्तिकरण का भाव पैदा होता है, वो गरीबी से लड़ने में उसकी मदद करता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने 12 करोड़ शौचालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क दिए गए 10 करोड़ गैस कनेक्शन, 80 करोड़ जरूरतमंदों को राशन, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन जैसी अनेक योजनाओं ने गरीब को ये भरोसा दिया है कि वो सम्मान के साथ जी सकते हैं। ऐसे ही प्रयासों की वजह से देश के 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करके आज अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने नियो मिडिल क्लास का एक ऐसा समूह तैयार किया है, जो भारत की ग्रोथ को नई ऊर्जा से भर रहा है।

माननीय सदस्यगण, भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा देश उतनी ही ऊंची उड़ान भरेगा। मेरी सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। सरकारी कर्मचारी भी मिडिल क्लास के अहम प्रतिनिधि हैं। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ये निर्णय, आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पचास प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है, जिसका व्यापक स्वागत हुआ है। मध्यम वर्ग का अपने घर का सपना पूरा करने के लिए भी मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। रेरा जैसा कानून बनाकर मध्यम वर्ग के सपने को सुरक्षा दी गई है। घर के लिए लोन पर सब्सिडी दी जा रही है। उड़ान योजना ने लगभग डेढ़ करोड़ लोगों का हवाई जहाज में उड़ने का सपना पूरा किया है। जन औषधि केंद्र में 80 प्रतिशत रियायती दरों पर मिल रही दवाओं से, देशवासियों के 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा बचे हैं। हर विषय की पढ़ाई के लिए सीटों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी का बहुत लाभ मध्यम वर्ग को मिला है। राष्ट्र निर्माण में करदाता के योगदान को मेरी सरकार ने सम्मान देते हुए टैक्स से जुड़े मसलों को आसान किया है। टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है। अब देश में पचहत्तर वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को, जिन्हें सिर्फ पेंशन मिलती है, आयकर रिटर्न दाखिल करने के संबंध में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में, यानी women led development में विश्वास करती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इक्यानवे लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। देश की दस करोड़ से भी अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। इन्हें कुल नौ लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित की गई है। मेरी सरकार का लक्ष्य देश में तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। आज एक करोड़ पंद्रह लाख से भी अधिक लखपति दीदी एक गरिमामय जीवन जी रही हैं। इनमें से लगभग 50 लाख लखपति दीदी, बीते 6 महीने में बनी हैं। ये महिलाएं एक उद्यमी के रूप में अपने परिवार की आय में योगदान दे रही हैं। Insurance for All की भावना के साथ कुछ महीने पूर्व ही बीमा सखी अभियान भी शुरू किया गया है। हमारी बैंकिंग और डिजी पेमेंट सखियाँ दूर दराज के इलाकों में लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कृषि सखियाँ नेचुरल फ़ार्मिंग को बढ़ावा दे रही हैं और पशु सखियों के माध्यम से हमारा पशुधन मज़बूत हो रहा है। ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। यह इस संसद के लिए गौरव का विषय है कि बड़ी संख्या में भारत की बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रही हैं और कॉरपोरेट कंपनियों का नेतृत्व भी कर रही हैं। मेरी सरकार के निर्णय के बाद बालिकाओं की भर्ती राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रारंभ हो गई है। नेशनल डिफेंस अकैडमी में भी महिला कैडेट्स की भर्ती शुरू हो गई है। हमारी बेटियाँ आज ओलंपिक में मेडल लाकर देश को भी गौरवान्वित कर रही हैं। मैं भारत की संसद के माध्यम से देश की नारी-शक्ति को विशेष बधाई देती हूँ।

माननीय सदस्यगण, पिछले एक दशक में देश के हर बड़े प्रयास का दायित्व आगे बढ़कर भारत के युवाओं ने उठाया है। आज हमारा युवा स्टार्टअप्स, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर फ़ील्ड में देश का नाम रोशन कर रहा है। MY Bharat पोर्टल के ज़रिये लाखों युवा राष्ट्र निर्माण के कार्यों से जुड़ रहे हैं। पिछले एक दशक में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने युवाओं को रोज़गार के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। पिछले दो वर्षों में सरकार ने, रिकॉर्ड संख्या में दस लाख स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। मेरी सरकार ने युवाओं के बेहतर कौशल और नए अवसरों के सृजन के लिए दो लाख करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृत किया है। एक करोड़ युवाओं के लिए इंटरशिप की व्यवस्था से युवाओं को ग्राउंड पर काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। आज देश में डेढ़ लाख से अधिक स्टार्टअप हैं जो इनोवेशन के स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। एक हज़ार करोड़ रुपए की लागत से स्पेस सेक्टर में वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। यानी फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में AI और डिजिटल तकनीक अपनाने में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग छिहत्तर से सुधर कर उनचालीस हो गई है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तैयार कर रही है। कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, इसीलिए मातृ भाषा में शिक्षा के अवसर दिये जा रहे हैं। विभिन्न भर्ती परीक्षाएं तेरह भारतीय भाषाओं में आयोजित कर, भाषा संबंधी बाधाओं को भी दूर किया गया है। बच्चों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए दस हज़ार से अधिक स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब्स खोली गई हैं। ? ईज ऑफ़ ड्रूंग रिसर्च? के लिए हाल ही में वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन स्कीम लायी गई है। इससे अंतरराष्ट्रीय शोध की सामग्री निशुल्क उपलब्ध हो सकेगी। पिछले एक दशक में उच्च शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ी है। इनकी गुणवत्ता में भी व्यापक सुधार हुआ है। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी - एशिया रैंकिंग में हमारे एक सौ तिरसठ विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के नये कैंपस का शुभारंभ कर शिक्षा में, भारत का पुराना गौरव वापस लाया गया है। वह दिन भी दूर नहीं जब भारत में निर्मित गगनयान में एक भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में जाएगा। कुछ दिन पहले स्पेस डॉकिंग में सफलता ने भारत के अपने स्पेस स्टेशन का मार्ग और

आसान कर दिया है। कुछ ही दिन पहले इसरो ने अपना सौवां लॉन्च करते हुये सैटेलाइट को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। मैं इस उपलब्धि के लिए भी इसरो को, और सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने देश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स वातावरण बनाने की दिशा में खेलो इंडिया स्कीम; टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानि TOPS; राष्ट्रीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जैसे कई कदम उठाए हैं। दिव्यांगों के लिए ग्वालियर में विशेष खेल केंद्र खोला गया है। भारत की टीमों ने चाहे ओलंपिक हो, या फिर पैरालंपिक, हर जगह बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हाल ही में विश्व शतरंज चैम्पियनशिप में भी भारत ने अपना परचम लहराया है। फिट इंडिया मूवमेंट चलाकर हम सशक्त युवाशक्ति का निर्माण कर रहे हैं।

माननीय सदस्यगण, विकसित भारत के निर्माण में किसान, जवान और विज्ञान के साथ ही अनुसंधान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा लक्ष्य भारत को ग्लोबल इनोवेशन पावरहाउस बनाना है। देश के शिक्षण संस्थाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पचास हज़ार करोड़ रुपए की लागत से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउन्डेशन स्थापित किया गया है। दस हज़ार करोड़ रुपए की लागत से 'विज्ञानधारा योजना' के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को आगे बढ़ाते हुए 'इंडिया एआई मिशन' प्रारम्भ किया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से भारत, इस फ्रंटियर टेक्नॉलाजी में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में स्थान बना सकेगा। मेरी सरकार, देश में 'बायो - मैन्यूफैक्चरिंग' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से BioE3 Policy लायी है। यह पॉलिसी भविष्य की औद्योगिक क्रांति का सूत्रधार होगी। बायो इकॉनामी का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग करना है जिससे पर्यावरण को संरक्षित करते हुए रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने अर्थव्यवस्था को पॉलिसी पैरालिसिस जैसी परिस्थितियों से उबारने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति के साथ काम किया है। कोविड और उसके बाद के हालात एवं युद्ध जैसी वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो स्थायित्व एवं resilience दिखाया है, वो उसके सशक्त होने का प्रमाण है। मेरी सरकार ने Ease of doing business को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वन नेशन वन टैक्स की भावना के तहत जीएसटी की व्यवस्था लागू की गई, जिसका फायदा सभी राज्यों को मिल रहा है। मेक इन इंडिया जैसी नीतियों के कारण अब बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के प्रॉडक्ट्स पर भी 'मेड इन इंडिया' के लेबल्स दिखने लगे हैं।

माननीय सदस्यगण, भारत के छोटे व्यापारी गाँव से लेकर शहरों तक, हर जगह आर्थिक प्रगति को गति देते हैं। मेरी सरकार छोटे उद्यमियों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए उन्हें स्वरोजगार के नए अवसर दे रही है। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम और ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स सभी प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरे कार्यकाल में, मेरी सरकार द्वारा मुद्रा ऋण की सीमा को दस लाख रुपए से बढ़ाकर बीस लाख रुपए करने का लाभ करोड़ों छोटे उद्यमियों को हुआ है। मेरी सरकार ने क्रेडिट एक्सेस को आसान बनाया है। इससे वित्तीय सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाया जा सका है। आज लोन, क्रेडिट कार्ड, बीमा जैसे प्रोडक्ट, सबके लिए आसानी से सुलभ हो रहे हैं। दशकों तक हमारे देश के रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाकर आजीविका चलाने वाले भाई-बहन बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रहे। आज उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है। डिजिटल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड के आधार पर उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए और लोन मिलता है। ओएनडीसी की व्यवस्था ने डिजिटल कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग की व्यवस्था को समावेशी बनाया है। आज देश में छोटे बिजनेस को भी आगे बढ़ाने का समान अवसर मिल रहा है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने दस वर्षों में प्रगति के जो नए अध्याय लिखे हैं, उनमें से एक स्वर्णिम सोपान भारत की डिजिटल क्रांति का भी है। आज भारत डिजिटल टेक्नॉलाजी की फ़्रील्ड में एक प्रमुख ग्लोबल प्लेयर

के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। दुनिया के बड़े देशों के साथ ही भारत में 5G सर्विसेस की शुरुआत इसका एक बड़ा उदाहरण है। भारत की यूपीआई टेक्नॉलाजी की सफलता से दुनिया के कई विकसित देश भी प्रभावित हैं। आज 50 प्रतिशत से ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। मेरी सरकार ने डिजिटल टेक्नॉलाजी को सामाजिक न्याय और समानता के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। डिजिटल पेमेंट कुछ लोगों या कुछ वर्गों तक सीमित नहीं है। भारत में छोटे से छोटा दुकानदार भी इस सुविधा का लाभ उठा रहा है। गाँव में भी बैंकिंग सेवाएँ और UPI जैसी वर्ल्ड क्लास टेक्नॉलाजी उपलब्ध है। भारत में पिछले 10 साल में बने पांच लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स सरकार की दर्जनों सुविधाएँ ऑनलाइन उपलब्ध करा रहे हैं। मेरी सरकार ने लोगों के जीवन पर सरकार का प्रभाव कम करने के लिए ई-गवर्नेंस को महत्व दिया है। डिजिटल सेवा की व्यवस्था ने लोगों को कभी भी, कहीं भी अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पाने और दिखाने की सुविधा दी है। तेज़ी से डिजिटलाइज़ होते हमारे समाज में आज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विषय साइबर सिक्योरिटी है। डिजिटल फ्रॉड, साइबर-क्राइम और डीप फेक जैसी टेक्नॉलाजी सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती भी बनी है। इन साइबर-क्राइम को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए रोज़गार की संभावनाएँ हैं। मेरी सरकार साइबर सिक्योरिटी में दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। इसके फलस्वरूप भारत ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में टियर-1 स्टेटस प्राप्त कर लिया है।

माननीय सदस्यगण, किसी भी देश का आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर न केवल उसके नागरिकों को एक बेहतर जीवन एवं देश को नई पहचान देता है, बल्कि देश को एक नया आत्मविश्वास भी देता है। बीते दशक में भारत ने वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के कई माइल स्टोन्स तय किए हैं। इस आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से दुनिया में भारत की छवि मजबूत हुई है, इन्वेस्टर्स का भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है, उद्योगों को बल मिला है और नए रोज़गार का निर्माण हो रहा है। मेरी सरकार देश के हर हिस्से को हाइवे, एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के द्वारा परियोजनाओं को पूरा करने की गति तेज हुई है। दस साल पहले, बुनियादी ढांचे का बजट लगभग दो लाख करोड़ रुपये था, जो पिछले बजट में बढ़कर ग्यारह लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। पिछले एक दशक के काम को आगे ले जाते हुए, पिछले छह महीनों में मेरी सरकार ने भविष्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश किया है। वाढवण में भारत के पहले डीप वाटर मेगा पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। छिहत्तर हज़ार करोड़ की लागत से बनने वाला ये पोर्ट विश्व के शीर्ष दस पोर्ट्स में से एक होगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना पूरी हो गई है और अब देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चेनाब ब्रिज का निर्माण हुआ है जो विश्व का सबसे ऊँचा रेल ब्रिज है। साथ ही आँजी ब्रिज, देश का पहला रेल केबल ब्रिज बना है। शिंकुन ला सुरंग पर काम भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। निकट भविष्य में पूरी होने पर ये विश्व की सबसे ऊँची सुरंग होगी। इससे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच बारहमासी संपर्क बना रहेगा। भारत का एविएशन सेक्टर तेज़ी से विकास कर रहा है। देश की एयरलाइन कम्पनियों ने सत्रह सौ से अधिक नए विमानों के ऑर्डर दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले विमानों के परिचालन के लिए हम एयरपोर्ट्स का विस्तार कर रहे हैं। पिछले एक दशक में देश में एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो गई है।

माननीय सदस्यगण, विकसित भारत को गति देने के लिए हमारे शहरों को स्मार्टर रेडी बनाना आवश्यक है। इस दिशा में मेरी सरकार ने शहरी सुविधाओं का आधुनिकीकरण कर उन्हें एनर्जी एफिशिएंट बनाने पर जोर दिया है। साथ ही नए शहरों के विकास की भी नींव रखी जा रही है। मेरी सरकार ने लगभग अठ्ठाइस हज़ार करोड़ रुपये के निवेश से देश भर में बारह इंडस्ट्रियल नोड और शहरों के पास सौ औद्योगिक पार्क बनाने का भी निर्णय लिया है। शहरी यातायात को सुगम बनाने के कार्य लगातार जारी हैं। दिल्ली, पुणे, ठाणे और बेंगलुरु में मेट्रो प्रोजेक्ट्स और अहमदाबाद-भुज रूट पर शुरू हुई नमो भारत रैपिड रेल सर्विसेज़ विकसित भारत के शहरों का स्वरूप हैं।

कुछ सप्ताह पूर्व ही दिल्ली में रिठाला-नरेला-कुंडली कॉरिडोर का काम शुरू हुआ है, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के बड़े सेक्शन में से एक होगा। मेरी सरकार के निरंतर प्रयास से दिल्ली में मेट्रो रूट लगातार बढ़ रहा है। 2014 में दिल्ली-NCR में मेट्रो का कुल नेटवर्क 200 किलोमीटर से भी कम था। अब ये बढ़कर दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। आज मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि भारत का मेट्रो नेटवर्क अब एक हजार किलोमीटर के माइलस्टोन को पार कर चुका है। भारत अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। लगभग आठ हजार करोड़ रुपये के खर्च से देश में बावन हजार इलेक्ट्रिक बस चलाने का भी निर्णय हुआ है। इससे शहरी इलाकों में सुगम और स्वच्छ यातायात की सुविधा मिलेगी और अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा। आसान कनेक्टिविटी और अर्बन टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए देश में पंद्रह रोपवे प्रोजेक्ट्स की योजना पर भी काम हो रहा है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार बहु-आयामी एवं समरस-सर्वस्पर्शी विकास की नीतियों पर काम करती आई है। इसीलिए, मेरी सरकार ने जितना बल फ़िज़िकल इन्फ़्रास्ट्रक्चर पर दिया है उतने ही सघन प्रयास सोशल इन्फ़्रास्ट्रक्चर क्रांति के लिए भी किए हैं। समाज के हर वर्ग तक सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचें, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। अस्पताल, इलाज और दवा की व्यवस्था के कारण एक सामान्य परिवार में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च निरंतर कम हो रहा है। देश में नागरिकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए एक लाख पचहत्तर हजार आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। देश में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या और इलाज में होने वाले खर्च को देखते हुए अनेक कैंसर दवाओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। सर्वाइकल कैंसर के लिए अब तक लगभग नौ करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। मेरी सरकार के प्रयासों से दिमागी बुखार से लड़ने में देश को काफी सफलता मिली है। इससे होने वाली मृत्यु दर अब घटकर छह प्रतिशत रह गयी है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी के मरीजों की संख्या भी घटी है। मेरा सभी देशवासियों और माननीय सांसदों से आग्रह है कि हम सब मिलकर टीबी मुक्त भारत के अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी व्यापक सुधार हुआ है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम की सही ट्रेकिंग रखने के लिए U-WIN पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर अब तक लगभग तीस करोड़ वैक्सीन खुराक दर्ज हो चुकी है। टेली मेडिसिन के माध्यम से तीस करोड़ से अधिक ई-टेली-कन्सल्टेशन से नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। सरकार अगले पाँच सालों में देश के मेडिकल कॉलेजों में पचहत्तर हजार नई सीटों के सृजन के लिए भी काम कर रही है। सरकार हेल्थ इन्फ़्रास्ट्रक्चर और मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। देश में नए बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइसेस के पार्क भी बनाए जा रहे हैं। इनमें रोजगार के अनेक नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

माननीय सदस्यगण, भारत में आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था हमारा लक्ष्य है। मेरी सरकार किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड तीन सौ बत्तीस मिलियन टन अनाज उत्पादन हुआ है। और आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध, दाल और मसालों का उत्पादक है। सरकार ने खरीफ़ और रबी फ़सलों के एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरी की है। पिछले एक दशक में धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खरीद पर 3 गुना ज्यादा राशि खर्च की गई है। पिछले 6 महीने में फसलों की जलवायु अनुकूल, बायो-फॉर्टिफाइड और अच्छी उपज देने वाली एक सौ नौ उन्नत प्रजातियाँ किसानों को सौंपी गई हैं। देश में कृषि इन्फ़्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कृषि इन्फ़्रास्ट्रक्चर फंड योजना के दायरे का विस्तार किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को और बढ़ावा मिलेगा। देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड्स को स्वीकृति दी गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में ही, किसानों को सस्ती दरों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष पैकेज की अवधि को बढ़ाया गया है। मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए ग्यारह एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है।

माननीय सदस्यगण, कुछ सप्ताह पूर्व ही भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरे हुए हैं। वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट भारत के लिए मेरी सरकार ने दो हज़ार करोड़ रुपये की लागत से 'मिशन मौसम' प्रारम्भ किया है, जिसका लाभ हमारे किसानों को भी मिलेगा। बाबासाहेब आंबेडकर के विजन पर चलते हुए, देश के सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए, मेरी सरकार ने दो ऐतिहासिक रिवर इंटरलिंगिंग परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाया है। चवालीस हज़ार करोड़ रुपये से अधिक लागत की केन-बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों ग्रामीण भाई-बहनों को लाभ मिलेगा। संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और पीने के पानी की आवश्यकता की पूर्ति होगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए बारह हज़ार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की गई है।

माननीय सदस्यगण, हमारी आठ लाख सहकारी संस्थाएं एवं उनके उन्तीस करोड़ हितधारक सदस्य, ग्रामीण भारत के करीब नब्बे प्रतिशत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीते वर्षों में शहरी क्षेत्रों में भी सहकारी संस्थाओं का विस्तार हुआ है। सहकारी सेक्टर के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरूप रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो रहे हैं। वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें भारत अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा।

माननीय सदस्यगण, जब हम राष्ट्र के विकास और उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, तो वास्तव में हम राष्ट्र के नागरिकों की क्षमता एवं उपलब्धियों का ही उल्लेख कर रहे होते हैं। आज देश के विकास में सबका साथ है, इसीलिए हम देश के सही सामर्थ्य का अनुभव कर पा रहे हैं। मेरी सरकार के प्रयासों का सबसे अधिक लाभ देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को मिल रहा है। आज़ादी के दशकों बाद भी हमारे जिस जनजातीय एवं आदिवासी समाज की उपेक्षा होती रही, मेरी सरकार ने उसके कल्याण को पहली प्राथमिकता दी है। 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' और 'पीएम-जनमन योजना' इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। देश भर में स्थापित चार सौ सत्तर से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से लगभग सवा लाख आदिवासी बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जा रही है। पिछले दस वर्षों में आदिवासी बहुल इलाकों में तीस नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। विशेष राष्ट्रीय मिशन चलाकर आदिवासी समुदाय की सिकल सेल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत लगभग पाँच करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जनजातीय विरासत को सहेजने के लिए भी मेरी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की एक सौ पचासवीं जयंती का पर्व पूरे देश में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण, विकसित भारत की एक महत्वपूर्ण कसौटी, देश का संतुलित विकास है। किसी क्षेत्र में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि वो विकास में पीछे छूट रहे हैं। मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों की इन्हीं भावनाओं को समझा, उनके दिल से दूरियों का भाव समाप्त किया। दस से अधिक शांति समझौते कर सरकार ने अनेक गुटों को शांति के मार्ग से जोड़ने का काम किया है। पूरा देश नॉर्थ ईस्ट के आठ राज्यों की संभावनाओं को देख सके, इस दिशा में, पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर के विकास के साथ-साथ सरकार ने देश के 'पूर्वोदय' यानि पूर्वी राज्यों के सर्वांगीण विकास की कार्य-योजना पर काम शुरू कर दिया है जिससे रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप में विकास की कई परियोजनाएं प्रारम्भ कर उन्हें राष्ट्र की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया वातावरण बना है। जम्मू कश्मीर में लोक सभा चुनाव एवं विधान सभा चुनाव अत्यंत शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुए। जम्मू कश्मीर के लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

माननीय सदस्यगण, राष्ट्र या समाज की सफलता समावेशी एवं सर्व-स्पर्शी तभी होती है जब वह सिद्धांतों से प्रेरित हो। इसीलिए, मेरी सरकार ने उन मौलिक सिद्धांतों को हमेशा अपनी कार्यनीति के केंद्र में रखा जिनका निर्देश हमारे संविधान ने दिया है। संविधान के आलोक में मेरी सरकार की प्रमुख सैद्धान्तिक प्रेरणा है - सेवा! मेरी सरकार मानती है कि 140 करोड़ देशवासियों की सेवा ही सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। इस दिशा में सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। समाज के पिछड़े वर्ग और सफ़ाई कर्मचारियों को आसान लोन मुहैया कराने के लिए पीएम सूरज योजना का विस्तार किया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिव्यांग जनों तक पहुंचाने के लिए एक करोड़ से अधिक दिव्यांग पहचान पत्र जारी किये गए हैं। स्वच्छता सैनिकों के लिए चलायी जा रही 'नमस्ते योजना' का विस्तार कर अब स्वच्छता का बीड़ा उठाने वाले भाई-बहनों को भी इसमें शामिल किया गया है। विकसित भारत की यात्रा में कोई भी छूटने ना पाए, इस ध्येय के अनुरूप मेरी सरकार सेचुरेशन अप्रोच के साथ काम कर रही है।

माननीय सदस्यगण, बीता दशक भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनः जागरण का दशक रहा है। हम अपनी विरासत पर गर्व और विकास के प्रति समर्पण के साथ ऐसा भविष्य गढ़ रहे हैं जहां संस्कृति और प्रगति साथ-साथ आगे बढ़ें। इस वर्ष हम, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक सौ पच्चीसवीं जयंती मनाएंगे। उन्होंने कहा था कि "सच्चा राष्ट्रवाद केवल भारत की भौतिक एकता नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने में है।" इसी कड़ी में भगवान महावीर का पच्चीस सौ पचासवाँ निर्वाण महोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। देश ने उत्साह से संत मीराबाई की पाँच सौ पच्चीसवीं जयंती भी मनाई। महाकवि संत तिरुवल्लुवर की स्मृति में कई देशों में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मेरी सरकार काशी-तमिल संगमम्, काशी-तेलुगू संगमम्, सौराष्ट्र-तमिल संगमम् जैसे सांस्कृतिक आयोजन करके देश की एकता को बढ़ावा दे रही है।

माननीय सदस्यगण, हमारी पांडुलिपियाँ हमारी धरोहर हैं। इनमें विशाल ज्ञान समाहित है जिसका मानव जाति के लाभ के लिए अध्ययन, शोध और उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पांडुलिपियों के डिजिटल इजेशन और संरक्षण का कार्य मिशन मोड पर प्रारंभ किया जा रहा है। देश की विरासत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारी समृद्ध भाषा-संस्कृति है। मुझे खुशी है कि सरकार ने असमी, मराठी, पाली, प्राकृत और बांग्ला भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। भारत की सभी भाषाओं में सरलता से संवाद के लिए AI की सहायता से भाषिणी प्लेटफॉर्म का देशवासी व्यापक उपयोग कर रहे हैं।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के प्रयासों से आज विश्व के सांस्कृतिक मंच पर भारत ने ग्लोबल लीडर की पहचान बनाई है। सभी एशियाई बौद्ध देशों को आपस में जोड़ने के लिए, मेरी सरकार ने पहली एशियाई बुद्धिस्ट कांफ्रेंस का आयोजन किया। पिछले वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की बैठक का आयोजन भी भारत में हुआ जिसमें एक सौ चालीस देशों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से पूरा विश्व आज भारत की योग परंपरा को अंगीकार कर रहा है।

माननीय सदस्यगण, प्रगति की भव्य इमारत को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए मजबूत स्तंभों की जरूरत होती है। भारत के विकास के लिए मेरी सरकार ने Reform, Perform और Transform के ऐसे ही तीन मजबूत स्तंभ बनाए हैं। आज ये शब्द पूरी दुनिया में भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का पर्याय बन गए हैं। सरकार ने संविधान के लागू होने से पहले बने कानूनों की विस्तृत समीक्षा की है। कई कानूनों को निरस्त या संशोधित किया जा रहा है ताकि पूरा तंत्र वर्तमान सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सके। सरकार अब तक पंद्रह सौ से अधिक पुराने अनावश्यक कानूनों को निरस्त कर चुकी है। गुलामी के कानूनों को हटाकर दंड संहिता के स्थान पर न्याय संहिता लागू की गई है। ?जन-विश्वास? और ?जन-भागीदारी? के साथ मेरी सरकार जनता का जीवन सुगम बनाने पर कार्य कर रही है। विवादों को निपटाने के लिए ?विवाद से विश्वास? की पहल

की गई है। इसी भावना के साथ सरकार ने चालीस हजार से अधिक नियमों को कम या सरल किया है और पैंतीस सौ प्रावधानों को अपराधमुक्त किया है। मेरी सरकार ने देश के अत्यन्त पिछड़े इलाकों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रारम्भ कर सुशासन का एक अनूठा प्रयोग किया है। इस कार्यक्रम से इन जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विभिन्न मापदंडों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यूएनडीपी की एक रिपोर्ट में इस पहल की बहुत सराहना की गई है। इस सफलता से प्रेरित होकर अब देश के पांच सौ आकांक्षी ब्लॉक में भी समग्र विकास हेतु अभियान प्रारम्भ किया गया है। सुशासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए i-GOT कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिससे सरकारी कर्मियों को अपनी दक्षता बढ़ाकर कर्मयोगी बनने का प्रोत्साहन मिल रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर सत्रह सौ पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और अब तक दो करोड़ से अधिक प्रशिक्षण पूर्ण किए गए हैं।

माननीय सदस्यगण, इस वर्ष देश सरदार वल्लभभाई पटेल की एक सौ पचासवीं जयंती मना रहा है। उनकी प्रेरणा से मेरी सरकार 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को लेकर आगे बढ़ रही है। देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। विशेषकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में हमें बहुत उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। हम 'मेक इन इंडिया' से 'मेक फॉर द वर्ल्ड' की ओर बढ़े हैं। इससे देश में रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। कुछ दिन पहले एक ऐतिहासिक पल में देश में बने दो युद्धपोतों और एक पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। देश में डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना और डिफेन्स स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देकर हम आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार को मजबूती दे रहे हैं। सीमाओं की रक्षा के साथ-साथ देश के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास भी हमारी रणनीति का अहम हिस्सा है। सीमा क्षेत्र की सड़कें और अटल टनल, सेला टनल, सोनमर्ग टनल जैसे आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से रक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। सीमा पर स्थित देश के प्रथम गांवों में 'वाइब्रेंट विलेज' कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के अंतिम चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। सरकार के प्रयासों से वामपंथी-उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या एक सौ छब्बीस से घटकर अब अड़तीस तक आ गई है।

माननीय सदस्यगण, वैश्विक अस्थिरता के वातावरण में भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिरता का स्तम्भ बनकर विश्व के सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। चाहे जी7 समिट हो, क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ हो या जी 20, भारत के सामर्थ्य, नीति और नीयत पर पूरे विश्व ने भरोसा जताया है। आज बड़े से बड़े वैश्विक मंच पर भी भारत अपने हितों को मजबूती के साथ आगे रखता है। जी 20 का सफल आयोजन और दिल्ली डिक्लेरेशन इसका उदाहरण है। तीसरी ग्लोबल साउथ समिट, भारत आसियान समिट और भारत कैरीकॉम समिट में हमने ग्लोबल साउथ से जुड़े विषयों को अभिव्यक्ति दी है। हमने समिट ऑफ द फ्यूचर में भारत का 'विजन फॉर फ्यूचर' रखा है। इसी माह मेरी सरकार द्वारा भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। प्रवासी भाई-बहनों की सुविधा-सहूलियत हमारी प्राथमिकता है, इसलिए छह नए दूतावास और चार नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया गया है। विश्व बंधु की छवि मजबूत करते हुए विश्व में कई आपदाग्रस्त इलाकों में भारत ने तुरंत सहायता भरा हाथ बढ़ाया है। भारत ने कई देशों के साथ अपना डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर साझा किया है और जन औषधि केंद्र स्थापित किए हैं।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए भी निर्णय ले रही है। हम देश को ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन जॉब्स की तरफ ले जा रहे हैं। 2030 तक पांच सौ गीगावॉट नॉन फॉसिल फ्रयूल एनर्जी क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बीते छह महीनों में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पचहत्तर हजार करोड़ रुपये की लागत से रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। अभी तक साढ़े सात लाख घरों में रूफटॉप सोलर की स्थापना की जा चुकी है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। 'राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' के तहत आठ लाख करोड़ रुपए का निवेश और

छह लाख से अधिक रोजगार का सृजन होगा। हम परमाणु ऊर्जा का विस्तार करने पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। मेरी सरकार, वाहन स्कैपिंग पॉलिसी लायी है, ताकि पुराने वाहनों का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा हो और इससे भी रोजगार के नए अवसर सृजित हों। इसी क्रम में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर "एक पेड़ मां के नाम" अभियान प्रारम्भ किया गया। इस पहल में करोड़ों देशवासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। इस अभियान की पूरे विश्व ने सराहना की है।

माननीय सदस्यगण, हमारा भारत 140 करोड़ आबादी वाला देश है। हमारे यहां भिन्न-भिन्न राज्य, भिन्न-भिन्न क्षेत्र, भिन्न-भिन्न भाषाएँ हैं, परंतु एक राष्ट्र के रूप में हमारी एक ही पहचान है - भारत। और हमारा एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है - विकसित भारत! आने वाले वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। इस संकल्प में देश के शहीदों की प्रेरणाएँ हैं, पूज्य बापू के मानवीय आदर्श हैं, और सरदार पटेल जैसी मां भारती की संतानों द्वारा हमें दिलाई गई एकता की शपथ है। हमें इन प्रेरणाओं को आगे रखते हुये एकता के इस सामर्थ्य से विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करना है। आइए, हम एक बार फिर एकता के संकल्प को दोहराएँ, और भारत के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हों! जब हम साथ मिलकर बढ़ेंगे तो हमारी भावी पीढ़ियाँ 2047 में अवश्य विकसित, सशक्त, समर्थ और समृद्ध भारत देखेंगी। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।

धन्यवाद, जय हिन्द,

जय भारत I

Hon?ble Members,

It gives me immense pleasure to address this session of Parliament. Just two months ago, we celebrated the 75th anniversary of adoption of our Constitution, and only a few days ago, the Indian Republic completed 75 years of its journey. This occasion will elevate India?s pride as the mother of democracy to new heights. On behalf of all the citizens of the country, I pay tribute to Babasaheb Ambedkar and all the framers of the Constitution.

Hon?ble Members, the historic festival of Mahakumbh is also underway in the country. Mahakumbh is a festival of India?s cultural tradition and social consciousness. Millions of devotees from across the country and the world have taken the holy dip at Prayagraj. I express my sorrow over the unfortunate incident that occurred on Mauni Amavasya and wish for the speedy recovery of the injured. A few days ago, we lost the former Prime Minister of the country, Dr. Manmohan Singhji. He served the nation as Prime Minister for ten years and was a long-time member of Parliament. I offer my heartfelt tribute to Manmohan Singhji.

Hon?ble Members, my government is infusing new energy through unprecedented achievements in this Amrit Kaal of India?s development journey. The pace of work has tripled in this third term. Today, the nation is witnessing major decisions and policies being implemented at an extraordinary speed, with the highest priority given to the poor, the middle class, the youth, women, and farmers. In the third term of my Government, concrete steps have been taken to achieve the goal of providing ?Housing for All?. Extending the Pradhan Mantri Awas Yojana, we have decided to provide new homes to an additional three crore families. A budget of 5,36,000 crore rupees has been allocated for this purpose. My government is committed to granting ownership rights of residential land to the rural poor and promoting financial inclusion. Under the SVAMITVA scheme, we have issued 2.25 crore property cards so far, of which approximately 70 lakh property cards have been distributed in the last six months alone. Under the PM Kisan Samman Nidhi scheme, 41,000 crore rupees has been disbursed to crores of farmers in recent months. The ?Dharti Aaba Tribal Village Utkarsh? campaign has been launched for the upliftment of five crore people from tribal communities, with an allocation of 80,000 crore rupees for this initiative. Under the Ayushman Bharat scheme, six crore senior citizens aged 70 years and above will receive health insurance, with a health cover of 5 lakh rupees per year. For small entrepreneurs, the loan limit under the MUDRA scheme has been increased from 10 lakh rupees to 20 lakh rupees. My government has placed special focus on education for the youth and creating new employment opportunities for them. The PM Vidyalakshmi scheme has been introduced to provide financial assistance to meritorious students for higher education. Additionally, one crore youth will be given internship opportunities in the top 500 companies. A new law has been enacted to prevent incidents of paper leaks and ensure transparency in recruitment. Following the spirit of prosperity through cooperation, the government has approved the proposal to establish the ?Tribhuvan? Cooperative University. Under the fourth phase of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, the government has sanctioned 70,000 crore rupees to connect 25,000 habitations. As the country celebrates the centenary year of Atal Ji?s birth, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana continues to embody his vision. Currently, 71 Vande Bharat, Amrit Bharat, and Namoo Bharat trains are operational across the country, with 17 new Vande Bharat trains and one Namoo Bharat train added in the past six months. The government has also made swift progress on critical issues like 'One Nation-One Election? and ?Waqf Act Amendment.'

Hon'ble Members, the decade-long tenure of my government has infused new energy into the journey of a 'Viksit Bharat'. In the vision of a 'Viksit Bharat'... there is the collective strength of public participation, a roadmap for the nation's economic progress, the power of technology in the form of a digital revolution, and the foundation of modern infrastructure. The government is steering India towards becoming the world's third-largest economy. To ensure that the journey towards 'Viksit Bharat' continues to be guided by the ideals of our Constitution, the government has placed four key principles—service, good governance, prosperity, and pride—at the core of its governance. The government is making rapid advances in its commitment to reform, perform, and transform. The guiding mantra of my government is 'Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas' and its goal is the creation of a 'Viksit Bharat'.

Hon'ble Members, development is truly meaningful when its benefits reach the person standing at the last rung of society. This is the essence of Antyodaya, to which my government has been unwaveringly committed. When poor people are provided with a dignified life, it instils a sense of empowerment that helps them fight poverty. Initiatives like the construction of 12 crore toilets under the Swachh Bharat Abhiyan, 10 crore free LPG connections under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, ration for 80 crore needy citizens, the Saubhagya Yojana, and the Jal Jeevan Mission have given poor the confidence that they can live with dignity. Due to such efforts, 25 crore people have overcome poverty and are moving forward in life. They have formed a Neo Middle Class, a group that is infusing new energy into India's growth journey.

Hon'ble Members, the economic progress of a nation like India is defined by the aspirations of the middle class and the fulfilment of those aspirations. The bigger the dreams of the middle class are, the higher the nation soars. It is my government that has, for the first time, openly acknowledged and appreciated the contributions of the middle class on every occasion. Government employees are also significant representatives of the middle class. Recently, my government decided to constitute the Eighth Pay Commission for the welfare of government employees. This decision will lay the foundation for substantial salary increase for government employees in the coming years. Additionally, the central government has decided to provide 50% assured pension to lakhs of employees under the Unified Pension Scheme, which has been widely welcomed. My government is equally committed to fulfilling the middle class's dream of owning a home. Laws like RERA have been introduced to safeguard their dreams. Subsidies on home

loans are being provided. Through the UDAN scheme, about 1.5 crore people have fulfilled their dream of flying in airplanes. Jan Aushadhi Kendras, offering medicines at 80% concessional rates have helped save more than 30,000 crore rupees for citizens. The multifold increase in the number of seats for education in various disciplines has significantly benefited the middle class. Acknowledging the role of taxpayers in nation-building, my government has simplified tax-related processes. The introduction of faceless assessments has enhanced transparency and reduced tax disputes. Senior citizens aged 75 years and above who get only pension now have the choice of deciding about filing their income tax returns.

Hon?ble Members, my government firmly believes in empowering the nation through women-led development. The Nari Shakti Vandan Adhiniyam, which provides reservation for women in the Lok Sabha and state assemblies, is a significant step in this direction. Under the National Rural Livelihood Mission, more than 91 lakh self-help groups (SHGs) are being empowered, connecting over 10 crore women across the country. These groups have received over 9 lakh crore rupees through bank linkages. My government has set a goal of 3 crore Lakhpati Didis. Today, over 1.15 crore Lakhpati Didis are leading dignified lives, with about 50 lakh becoming Lakhpati Didis in just the past six months. These women are contributing to their family incomes as entrepreneurs. With the spirit of ?Insurance for All,? the Bima Sakhi campaign was launched a few months ago. Our Banking and Digi-Payment Sakhis are playing a crucial role in connecting remote areas with the financial system. Meanwhile, Krishi Sakhis are promoting natural farming, and Pashu Sakhis are strengthening our livestock resources. The Drone Didi Yojana has become a medium for the economic and technological empowerment of women. It is a matter of pride for this Parliament that India?s daughters are now flying fighter jets, joining the police force, and leading corporate companies. Following my government?s decision, girls have started enrolling in National Military Schools and National Defence Academy as cadets. Our daughters are also making the nation proud by winning medals in the Olympics. Through this Parliament, I extend my heartfelt congratulations to the ?Nari Shakti?.

Hon?ble Members, over the past decade, India?s youth have come forward to take up the responsibility of driving every major national effort. Today, our youth are making the country proud in every field, from start-ups and sports to space exploration. Lakhs of young people are actively participating in nation-building efforts through the MY Bharat Portal. Initiatives like Make in India, Atmanirbhar Bharat, Startup India, Stand-Up India, and Digital India have created numerous

employment opportunities for the youth. In the past two years, the government has provided a record 10 lakh permanent government jobs. To enhance skills and create new opportunities for the youth, my government has approved a 2 lakh crore rupee package. An internship program for 1 crore youth will provide them with hands-on experience in real-world work environments. India now has over 1.5 lakh start-ups, which are emerging as pillars of innovation. To boost the space sector, a 1,000 crore rupees venture capital fund has been launched. In the QS World Future Skills Index 2025, India has risen to second place globally, showcasing leadership in AI and digital technology adoption in the Future of Work category. Similarly, India's rank in the Global Innovation Index has improved significantly, moving up from 76 th to 39 th position.

Hon'ble Members, through the National Education Policy, my government is establishing a modern education system for students. To ensure no one is deprived of education, opportunities for learning in mother tongues are being provided. Additionally, various recruitment exams are being conducted in 13 Indian languages, eliminating language barriers. To foster innovation among children, over 10,000 Atal Tinkering Labs have been established in schools. For enhancing the Ease of Doing Research, the One Nation-One Subscription Scheme has recently been introduced, offering free access to international research materials. Over the past decade, the number of higher education institutions has increased significantly, and their quality has also improved. In the QS World University Asia Rankings, 163 Indian universities have been included. The inauguration of the new Nalanda University campus has revived India's ancient glory in education. The day is not far when an Indian citizen will travel to space aboard the indigenously developed Gaganyaan spacecraft. The recent success in space docking has further paved the way for India to establish its own space station. Just a few days ago, ISRO conducted its 100 th launch, successfully placing the satellite in orbit. I congratulate ISRO and all the citizens of the country for this achievement.

Hon'ble Members, my government has taken significant steps to create a world-class sports ecosystem in the country. Initiatives like the Khelo India Scheme, the Target Olympic Podium Scheme (TOPS), and the establishment of the National Sports University are contributing to this vision. A special sports centre for Divyang athletes has been opened in Gwalior. India's teams, whether at the Olympics or the Paralympics, have consistently delivered outstanding performances. Recently, India also achieved remarkable success at the World Chess Championship. Through the Fit India Movement, we are building a strong and empowered youth force.

Hon'ble Members, in building a 'Viksit Bharat', the role of research along with the role of farmers, soldiers and science is of immense importance. Our goal is to establish India as a global innovation powerhouse. To promote research in educational institutions, the National Research Foundation has been established with an outlay of 50,000 crore rupees. Additionally, 10,000 crore rupees is being invested to foster innovation in science and technology under the Vigyan Dhara Yojana. India's contribution in the field of Artificial Intelligence is being elevated through the launch of the India AI Mission. The National Quantum Mission aims to position India among the leading nations in the field of frontier technology. My government has introduced the BioE3 Policy to boost bio-manufacturing. This policy will serve as the facilitator for the next industrial revolution. The focus of bio-economy is on the efficient utilization of natural resources to create new employment opportunities while preserving the environment.

Hon'ble Members, my government has worked with strong determination to lift the economy out of a state of policy paralysis. Despite global concerns such as the COVID-19 pandemic, its aftermath, and war-related uncertainties, the Indian economy has demonstrated remarkable stability and resilience, proving its strength. My government has implemented several significant measures to promote Ease of Doing Business. With the spirit of 'One Nation, One Tax?', the GST system was introduced, which has been benefiting all states across the country. Due to policies like Make in India, many major global brands now proudly display the label 'Made in India' on their products.

Hon'ble Members, India's small traders, from villages to cities, play a vital role in driving economic progress. My government considers small entrepreneurs as the backbone of the economy and is committed to providing them with new opportunities for self-employment. The Credit Guarantee Scheme for MSMEs and the establishment of e-commerce export hubs are promoting various industries. During this third term, the loan limit under the MUDRA scheme has been increased from 10 lakh rupees to 20 lakh rupees, benefiting crores of small entrepreneurs. My government has made credit access easier, thereby democratizing financial services. Today, products like loans, credit cards, and insurance are easily accessible to everyone. For decades, our brothers and sisters earning their livelihoods as street vendors remained excluded from the formal banking system. Today, they are benefiting from the PM SVANidhi Yojana, which allows them to access additional loans to expand their businesses based on their digital transaction records. The ONDC initiative has made digital commerce more

inclusive. Small businesses now have equal opportunities to grow in the online shopping ecosystem.

Hon?ble Members, my government, in the past ten years, has written new chapters of progress, one of which is the golden milestone of India?s digital revolution. Today, India has emerged as a major global player in the field of digital technology. The launch of 5G services in India, alongside other leading nations, stands as a significant milestone in this journey. India?s UPI technology has also impressed many developed countries. More than 50% of the world?s real-time digital transactions now take place in India. My government has utilized digital technology as a tool for social justice and equality. Digital payments are no longer confined to select individuals or classes. Today, even the smallest shopkeepers in India benefit from this facility. Banking services and world class technology such as UPI are now accessible in villages as well. Over the last ten years, more than 5 lakh Common Service Centres have been established, providing citizens with access to dozens of government services online. To minimize government interference in people?s daily lives, my government has emphasized e-governance. For instance, DigiLocker has enabled individuals to access and display their important documents anytime, anywhere. However, in an increasingly digital society, cybersecurity has become a crucial issue of national importance. Digital fraud, cybercrime, and emerging technologies like deep fakes pose challenges to our social, economic, and national security. My government has taken numerous measures to control these cyber threats, creating opportunities for employment in the field of cybersecurity for the youth. My government is continuously working to ensure competence in cybersecurity. As a result of these efforts, India has achieved Tier-1 status in the Global Cybersecurity Index.

Hon?ble Members, the modern infrastructure of any country not only provides its citizens with a better quality of life and gives the nation a new identity but also instils a renewed sense of confidence in the country. Over the past decade, India has achieved several milestones in constructing world-class infrastructure. This modern infrastructure has strengthened India?s image globally, increased investors? trust in the nation, boosted industries, and created new employment opportunities. My government is working in mission mode to connect every part of the country with highways and expressways. The PM Gati Shakti National Master Plan has accelerated the pace of project completion. Ten years ago, the budget for capex was around 2 lakh crore rupees, which has now increased to over 11 lakh crore rupees in the last budget. Continuing the progress of the last decade, my

government has made record investments in the past six months in infrastructure for the future. The foundation has been laid for India's first deep-water mega port at Vadhavan. This port, being built at a cost of 76,000 crore rupees, will rank among the top ten ports in the world. I am pleased to inform you that the Udhampur-Srinagar-Baramulla rail link project has been completed, connecting the nation from Kashmir to Kanyakumari through railway line. Under this ambitious project, the Chenab Bridge has been constructed, which is the highest railway bridge in the world. Additionally, India's first rail cable bridge, the Anji Bridge, has been completed. Work on the Shinkun La tunnel is also progressing successfully. Upon completion in the near future, it will be the world's highest tunnel, ensuring year-round connectivity between Ladakh and Himachal Pradesh. India's aviation sector is growing rapidly. The country's airline companies have placed orders for more than 1,700 new aircraft. We are expanding airports to operate such a large fleet. Over the past decade, the number of airports in the country has doubled.

Honorable Members, to accelerate the journey towards a Viksit Bharat, it is essential to make our cities future-ready. In this direction, my government has focused on modernizing urban amenities and making them energy-efficient. Simultaneously, the foundation is being laid for the development of new cities. My government has decided to invest approximately 28,000 crore rupees to establish 12 industrial nodes and build 100 industrial parks near cities across the country. Efforts to streamline urban transportation are continuously underway. Metro projects in Delhi, Pune, Thane, and Bengaluru, along with the recently launched Nammo Bharat Rapid Rail Services on the Ahmedabad-Bhuj route, are shaping the cities of a Viksit Bharat. Just a few weeks ago, work began on the Rithala-Narela- Kundli corridor in Delhi, which will be one of the major sections of the Delhi Metro network. The metro routes in Delhi are expanding rapidly due to my government's continuous efforts. In 2014, the total metro network in Delhi-NCR was less than 200 kilometres. Now, it has more than doubled. Today, I am extremely pleased to share that India's metro network has crossed the milestone of 1,000 kilometres. India has now become the third largest country in the world in terms of metro networks. Additionally, the decision to deploy 52,000 electric buses in the country, at an estimated cost of 8,000 crore rupees, will provide smooth and clean urban transportation. This initiative will also create numerous employment opportunities. To enhance connectivity and promote urban tourism, work is also underway on 15 ropeway projects across the nation.

Hon?ble Members, my government has consistently worked on policies of multi-dimensional and inclusive development. Therefore, while emphasizing on physical infrastructure, equal efforts have also been made by my government for a social infrastructure revolution. Providing affordable, accessible, and quality healthcare to every section of society is a top priority for my government. With improved hospital facilities, treatment options, and the availability of medicines, healthcare expenses for ordinary families are steadily decreasing. To ensure that better healthcare services reach citizens, 1,75,000 Ayushman Arogya Mandirs have been established across the country. Considering the rising number of cancer patients and the high cost of treatment, several cancer drugs have been exempted from customs duty. Nearly 9 crore women have been screened for cervical cancer. Due to the efforts of my government, significant progress has been made in combating encephalitis, with the mortality rate due to this disease reduced to 6%. Under the National TB Eradication Programme, the number of TB patients has also decreased. I urge all citizens and Hon?ble MPs to contribute towards the success of the TB-free India campaign. India has also seen substantial improvements in maternal and infant mortality rates. To ensure tracking of vaccination programmes for pregnant women and children, the U-WIN portal has been launched. So far, around 30 crore vaccine doses have been recorded on this platform. Through telemedicine, over 30 crore e-teleconsultations have provided healthcare benefits to citizens. The government is also working on creating 75,000 new seats in medical colleges over the next five years. The government is boosting health infrastructure and medical equipment manufacturing. New bulk drug and medical devices parks are being developed in the country, creating numerous employment opportunities.

Hon?ble Members, a modern and self-reliant agricultural system in India is our goal. My government is working with dedication to ensure fair prices of crops to farmers and to increase their income. In 2023-24, India achieved a record production of 332 million tons of foodgrains. Today, India is the largest producer of milk, pulses, and spices in the world. The government has consistently increased the Minimum Support Price (MSP) for both Kharif and Rabi crops. Over the past decade, spending on the procurement of rice, wheat, pulses, oilseeds, and coarse grains has tripled. In the past six months, 109 climate-resilient, bio-fortified, and high-yielding advanced crop varieties have been released to farmers. To strengthen agricultural infrastructure, the scope of the Agriculture Infrastructure Fund Scheme has been expanded. This initiative will boost employment opportunities in rural areas. To enhance oilseed production and achieve self-reliance in edible oils, a National Mission on Oilseeds has been approved. A

National Mission is also being implemented to promote Natural Farming. Earlier this year, the duration of the special package for ensuring availability of DAP fertilizer at affordable rates to farmers was extended. To promote fisheries, 11 Integrated Aqua Parks are being established.

Hon?ble Members, a few weeks ago, the India Meteorological Department completed 150 years. To build a weather-ready and climate-smart India, my government has launched the "Mission Mausam" at a cost of 2,000 crore rupees, which will also benefit our farmers. Following the vision of Babasaheb Ambedkar, my government has made headway on two historic river interlinking projects to provide irrigation and drinking water in the drought-affected areas of the country. The Ken-Betwa Link Project, with a cost of over 44,000 crore rupees, will benefit millions of brothers and sisters in rural areas of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. The revised Parbati-Kalisindh-Chambal Link Project will address irrigation and drinking water needs in Rajasthan and Madhya Pradesh. An additional 12,000 crore rupees have been sanctioned to expedite the completion of the Polavaram Irrigation Project.

Hon?ble Members, our 8 lakh cooperative societies and their 29 crore stakeholder members represent nearly 90% of rural India. In recent years, cooperative societies have also expanded in urban areas. Various initiatives taken for economic empowerment of the cooperative sector are creating numerous employment opportunities. The year 2025 is being celebrated as the International Year of Cooperatives, and India will play a significant role in this global initiative.

Hon?ble Members, when we discuss the nation?s development and achievements, we are essentially highlighting the capabilities and accomplishments of its citizens. Today, there is collective participation of all in the development of the nation and that is why we are able to realize its true potential. The greatest beneficiaries of my government?s efforts have been the Dalit, backward, and tribal communities. For decades after independence, our tribal communities faced neglect. My government has prioritized their welfare. The "Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan" and the "PM- JANMAN Yojana" are direct examples of this initiative. Nearly 1.25 lakh tribal children are receiving quality education through more than 470 Eklavya Model Residential Schools. In the last 10 years, 30 new medical colleges have been established in tribal-dominated areas. A special National Mission is addressing health issues related to sickle cell within tribal communities, with screening of around 5 crore individuals already completed. My government has undertaken

several initiatives to preserve tribal heritage. This year, the 150 th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda is being celebrated across the country as Janjatiya Gaurav Varsh.

Hon?ble Members, a significant measure of ?Viksit Bharat? is balanced development of the country. No region should feel left behind in the journey of progress. My government is conscious of the aspirations of the people of the North East and has worked to eliminate their sense of alienation. Through more than 10 peace agreements, several factions have been brought onto the path of peace. To showcase the potential of the eight states of the North East to the entire country, the first-ever Ashtalakshmi Mahotsav was organized. Along with the development of the North East, the government has initiated a comprehensive development plan for the ?Purvodaya? or the eastern states, which will also create new employment opportunities. In Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep, several developmental projects have been launched, according these regions a crucial role in the nation?s progress. After the abrogation of Article 370, there is a conducive environment for development in Jammu & Kashmir. Both the Lok Sabha and Vidhan Sabha elections were conducted in a peaceful manner in Jammu & Kashmir. The people of Jammu & Kashmir deserve commendation for this achievement.

Hon?ble Members, the success of a nation or society is inclusive and all-encompassing only when it is guided by principles. Therefore, my government has always placed the fundamental principles outlined by our Constitution at the core of its policies. In the light of the Constitution, the primary ideological inspiration of my government is ?Service?. My government firmly believes that serving 140 crore citizens is its foremost duty, and it is working with utmost sensitivity in this direction. To provide easy loans to the backward sections of society and sanitation workers, the scope of the PM-Suraj Yojana has been expanded. To ensure the benefits of government schemes reach differently-abled individuals, over 1 crore Divyang ID cards have been issued. The ?Namaste Yojana?, launched for sanitation workers, has been extended to include all those who take up the noble responsibility of cleanliness. With the goal to ensure that no one is left behind in the journey of a ?Viksit Bharat?, my government is working with a saturation approach.

Hon?ble Members, the past decade has been a period of revival of India?s cultural consciousness. With pride in our heritage and dedication to progress, we are shaping a future where culture and development move forward together. This

year, we will celebrate the 125 th birth anniversary of Dr. Syama Prasad Mookerjee, who said, "True nationalism lies not only in the physical unity of India but in strengthening its cultural unity." In the same spirit, the 2,550 th Nirvana Mahotsav of Lord Mahaveer was celebrated with reverence, and the 525 th birth anniversary of Sant Mirabai was enthusiastically observed across the country. Cultural centres are being established in several countries in memory of the great poet-saint Thiruvalluvar. My government is promoting national unity through cultural initiatives like Kashi-Tamil Sangamam, Kashi-Telugu Sangamam, and Saurashtra-Tamil Sangamam.

Honorable Members, our manuscripts are a priceless heritage, containing vast knowledge that needs to be studied, researched, and utilized for the benefit of humanity. The process of digitizing and preserving these manuscripts using advanced technology is being initiated on mission mode. A significant pillar of the nation's heritage is our rich linguistic culture. I am pleased to inform you that the government has granted Classical Language status to Assamese, Marathi, Pali, Prakrit, and Bengali. For easy communication in all languages of India, the language platform Bhashini powered by AI is being widely used by the citizens of the country.

Honorable Members, through the efforts of my government, India has established its identity as a global leader on the cultural stage. To connect all Asian Buddhist countries, my government organized the first Asian Buddhist Conference. Last year, India also hosted the World Heritage Committee's meeting, with participation from 140 countries. Through the celebration of International Yoga Day, the entire world is now embracing India's rich tradition of yoga.

Honorable Members, to take the grand edifice of progress to new glories, strong pillars are required. For India's development, my government has established three strong pillars of Reform, Perform and Transform. Today, these words have become synonyms of India's new governance model across the world. The government has conducted an extensive review of laws enacted before the Constitution came into force. Many laws are being repealed or amended to ensure that the entire system can meet the current social and economic challenges. So far, the government has repealed more than 1,500 obsolete laws. By removing colonial-era laws, a "Nyaya Sanhita" has been introduced in place of the Penal Code. With "Jan Vishwas" (public trust) and "Jan Bhagidari" (people's participation), my government is working to make the lives of citizens better. The "Vivad se

Vishwas? initiative has been launched to resolve disputes. In the same spirit, over 40,000 regulations have been simplified or reduced and 3,500 provisions have been decriminalized. My government has initiated the Aspirational Districts Programme in the country?s most backward areas, implementing a unique experiment in good governance. This programme has led to remarkable progress in health, nutrition, agriculture, social development, and education in these districts. A UNDP report has praised this initiative. Inspired by this success, the government has now launched a campaign for the holistic development of 500 aspirational blocks. Focusing on good governance, the i-GOT Karmayogi Digital Platform has been created, encouraging government employees to enhance their skills and become true Karmayogis. This platform offers 1,700 courses, and more than 2 crore course completions have taken place.

Hon?ble Members, this year, the country is celebrating the 150 th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. Inspired by his vision, my government is moving ahead with the principle of ?Nation First?. To ensure defence of the country?s borders and internal security, the government has undertaken historic initiatives. We have seen highly encouraging results in achieving self-reliance particularly in the defence sector. From Make in India, we have transitioned to Make for the World, which is also generating new employment opportunities across the country. In a historic moment, two warships and a submarine built in India were recently commissioned into the Indian Navy. We are strengthening self-reliance and self-employment by establishing the Defence Industrial Corridor and promoting defence start-ups. Along with securing the borders, the development of border areas is also a key component of our strategy. Roads in border areas, along with modern infrastructure like the Atal Tunnel, Sela Tunnel, and Sonamarg Tunnel, have enhanced both defence capabilities and tourism. The Vibrant Villages Programme has been launched in the country?s first villages located along the border. The final phase of eliminating Left-wing Extremism has also begun. Due to the government?s efforts, the number of districts affected by Left-wing Extremism has reduced from 126 to 38 today.

Hon?ble Members, in an environment of global instability, India is emerging as a pillar of economic, social, and political stability, setting an example for the world. Whether it is the G7 Summit, QUAD, BRICS, SCO, or G20, the world has placed its trust in India?s strength, policy, and intent. Today, India firmly presents its interests even on the largest global platforms. The successful hosting of the G20 Summit and the Delhi Declaration are prime examples. At the Third Global South Summit,

India-ASEAN Summit, and the India-CARICOM Summit, we have raised the voice on issues related to the Global South. We have also presented India's 'Vision for the Future' at the Summit of the Future. Earlier this month, my government organized the Pravasi Bharatiya Divas in Bhubaneswar. The welfare and convenience of our brothers and sisters of the diaspora remain a priority, which is why my government has decided to open six new embassies and four new consulates. Strengthening India's image as a 'Vishwa Bandhu', the country has extended immediate assistance to many disaster-stricken areas across the world. India has shared its Digital Public Infrastructure with several nations and set up Jan Aushadhi Kendra.

Honorable Members, my government is making decisions keeping in mind not only the present generation but also the future generations. We are steering the nation towards a green future and green jobs. Several significant decisions have been taken in the last six months towards achieving the target of 500 GW non-fossil fuel energy capacity by 2030. Under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, rooftop solar systems are being installed at a cost of 75,000 crore rupees. So far, over 7.5 lakh homes have installed rooftop solar systems, creating numerous job opportunities. The National Green Hydrogen Mission will have an investment of 8 lakh crore rupees and generate over 6 lakh jobs. We are also accelerating efforts to expand nuclear energy. My government has introduced the Vehicle Scrapping Policy to ensure scientific disposal of old vehicles, which will also generate new employment opportunities. In line with this, the 'Ek Ped Maa ke Naam' campaign was launched on World Environment Day 2024. Millions of citizens have enthusiastically participated, and this initiative has been appreciated worldwide.

Honorable Members, our Bharat is a country of 140 crore people. We have diverse states, diverse regions, and diverse languages, yet as one nation, we have only one identity - Bharat. And we have only one resolution, one goal - 'Viksit Bharat'! We are all firmly committed to making India a developed Nation in the coming years. This resolution is inspired by the sacrifices of the martyrs of the nation, the compassionate ideals of revered Bapu, and the oath of unity administered to us by the sons of Mother India like Sardar Patel. We must carry forward these inspirations and, with the strength of unity, fulfill the commitment of a Viksit Bharat. Let us once again reaffirm our resolution of unity and commit ourselves to realizing the dreams of India! When we move forward together, our future generations will surely witness a developed, empowered, capable, and prosperous Bharat in 2047.

I wish you all the very best.

Thank you. Jai Hind! Jai Bharat!
